



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 1994/वैशाख 20, 1916  
No. 197] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 1994/VAISAKHA 20, 1916

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

-(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1994

सा.का.नि. 444(अ).—केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 23 और धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1.(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1994 है

(ii) ये 12 नवम्बर, 1991 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 3ब के पश्चात् निम्न-लिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु उपरोक्त सेवानिवृत्ति संबंधी फायदे ऐसी धारा तभी समझे जाएंगे जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अर्थान कर लगाया जा सके।”

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

उक्त संशोधन को इस कारण से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है कि पूर्वोक्त सेवानिवृत्ति संबंधी फायदे भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 12-11-91 से दिए गए थे। यह विनिश्चय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) का धारा 23 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अन्तर्गत किया गया है कि इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित फायदे उमा तारीख, अर्थात् 12-11-1991 से ही दिए जाएं। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना नहीं है।

[सं. एन-11025/55/90-न्याय]

महीपाल सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), पृष्ठ 1161 (गृह मंत्रालय सं. 15/6/58-न्यायिक 1) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 935, तारीख 4 अगस्त, 1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा उनमें संशोधन किए गए:—

1. सा.का.नि. सं. 1366, तारीख 18-12-74
2. सा.का.नि. सं. 634, तारीख 22-4-76
3. सा.का.नि. सं. 854, तारीख 1-8-80
4. सा.का.नि. सं. 1176(अ), तारीख 4-11-86
5. सा.का.नि. सं. 680(अ), तारीख 12-11-1991
6. सा.का.नि. सं. 559(अ), तारीख 27-5-92
7. सा.का.नि. सं. 779(अ), तारीख 25-9-92
8. सा.का.नि. सं. 381(अ), तारीख 20-4-93

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 1994

G.S.R. 444(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 23 and 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely :—

1. (i) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 1994.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 12th day of November, 1991.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, after Rule 3B, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the above retiral benefits shall not be deemed to be income, liable to tax under the Income Tax Act, 1961.”

Explanatory Memorandum

The said amendment is being made retrospectively for the reason that the aforesaid retiral benefits had been extended to the retired Judges of the Supreme Court of India with effect from 12-11-91. This decision has been taken in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 23 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958) to extend the benefits proposed by this Notification from the same date i.e. 12-11-91. It is certified that by giving retrospective effect, nobody's interest is likely to be adversely affected.

[No. L-11025/55/90-Jus.]

M. P. SINGH, Jt. Secy.

---

Foot Note : Principal Rules published vide Notification No. GSR 935 dated 4-8-1959—Gazette of India Part-II, Section 3, Sub section (i), page 1161 (Ministry of Home Affairs No. 15/6/58-Judl. I).

1. GSR No. 1366, dtd. 18-12-74.
2. GSR No. 634, dtd. 22-4-76
3. GSR No. 854 dtd. 1-8-80
4. GSR No. 1176(E), dtd. 4-11-86
5. GSR No. 680(E), dtd. 12-11-91
6. GSR No. 559(E), dtd. 27-5-92
7. GSR No. 779(E), dtd. 25-9-92
8. GSR No. 381(E), dtd. 20-4-93